साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 28 मार्च-03 अप्रैल 2022, वर्ष-7, अंक-52

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

तीन दिन के अंदर एक ही बार में बेचना होगा गेहूं, समर्थन पर अब 28 मार्च से 4 अप्रैल तक खरीदी

उपज बेचने किसानों को करनी होगी ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग

भोपाल। संवाददाता

समर्थन मूल्य गेहूं बेचने वालों के लिए यह काम की खबर है। पहले 25 मार्च से गेहूं खरीदी शुरू होने वाली थी, लेकिन अब 28 मार्च और 4 अप्रैल से होगी। इस बार दो नए बदलाव हुए हैं। पहला, किसानों को ऑनलाइन स्लॉट बुक कराना पड़ेगा। स्लॉट बुकिंग के बाद वे 3 दिन के अंदर गेहूं लेकर सेंटर पर पहुंचेंगे। दूसरा, किसान को पूरा गेहूं एक ही बार में बेचना होगा। इंदौर-उज्जैन संभाग में 28 मार्च से ही गेहूं खरीदी होने लगेगी, जबकि भोपाल, जबलपुर-ग्वालियर समेत अन्य संभागों में किसान 4 अप्रैल से गेहूं बेच सकेंगे। गेहूं खरीदी सोमवार से शुक्रवार के बीच ही की जाएगी।

किसान खुद के मोबाइल से स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केंद्र, इंटरनेट कैफे, खरीदी केंद्र से भी बुकिंग हो सकेगी।

देने होंगे कुछ पैसे

किसान खुद अपने मोबाइल या कम्प्यूटर सिस्टम से स्लॉट बुक करते हैं, तो उन्हें चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केंद्र, इंटरनेट कैफे से बुकिंग कराते हैं, तो कुछ रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसके लिए सरकार ने राशि तय नहीं की है।

दो बड़े बदलाव

स्लॉट बुकिंग सिस्टम पहली बार आया है। किसान खुद ही केंद्र चुन सकते हैं। पहले एसएमएस आते थे और उस हिसाब से किसान गेहूं बेचने जाते थे। इस बार एक ही बार में पूरा गेहूं बेचना होगा। पहले ऐसा नहीं था। यदि किसी का 150 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ, तो किसान उसे दो-तीन हिस्सों में भी बेचने के लिए केंद्र पर जा सकते थे।

बुकिंग की वैधता 3 दिन| सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक स्लॉट बुक कर सकेंगे। स्लॉट बुकिंग की वैधता 3 दिन रहेगी। ऑनलाइन तरीके से होने वाली बुकिंग सिर्फ सोमवार से शुक्रवार के बीच ही होगी। किसान शनिवार और रविवार को बुकिंग नहीं करा सकेंगे।

दिक्कत आए तो जाएं केंद्र| स्लॉट बुकिंग में कोई दिक्कत आए, तो किसान पास के खरीदी केंद्र पर जा सकते हैं। वहां पर बुकिंग हो जाएगी। इसे लेकर अभी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया है। किसान अपनी तहसील के किसी भी सेंटर पर गेहूं बेच सकेंगे।

कब-कहां बिकेगी उपज

इंदौर और उज्जैन संभाग में सरकार 28 मार्च से 10 मई के बीच गेहूं की खरीदी करेगी। इनमें इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच और आगर शामिल हैं। नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर, भोपाल और चंबल संभाग में 4 अप्रैल से 16 मई तक खरीदी होगी। इनमें भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले शामिल हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध : हमारे गेहूं की विदेशों में डिमांड, विश्व की मंडियों में अपनी चमक बिखेरेगा गेहूं

दो साल से गोदामों पड़ा गेहूं निर्यात करेगा मध्यप्रदेश

-सीएम ने केंद्रीय मंत्री व गेहूं निर्यातकों के साथ की बैठक

भोपाल। संवाददाता

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण मध्यप्रदेश के गोदामों में दो साल से रखे एक करोड़ टन गेहूं की भी किस्मत खुल गई है। इसमें से 40 से 45 लाख टन गेहूं तुरंत निर्यात होगा। निर्यात मात्रा 70 लाख टन तक जा सकती है। यह पहला मौका है जब राज्य सरकार के गोदामों में भरे गेहूं का उठाव का मौका आया है। दरअसल, युद्ध के कारण यूरोपीय देशों में गेहूं नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए भारतीय राज्यों में गेहूं की डिमांड बढ़ गई है। मप्र को खास फायदा इस तरह भी हो रहा है, क्योंकि गोदामों में दो साल से भरा पड़ा गेहूं सरकार के लिए बड़ी समस्या बन रहा था। इस गेहूं की खरीद का सरकार पर 31 मार्च 2022 की स्थिति में 50 हजार करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है, जिसका हर रोज का 13 से 14 करोड़ रुपए ब्याज बैंकों में भरना पड़ रहा है। हालांकि गेहूं निर्यात से स्थिति सुधरेगी। सरकार का कर्ज 50 हजार करोड़ से घटकर 35 हजार करोड़ रुपए तक आ सकता है और ब्याज भी रोजाना सात करोड़ तक घट जाएगा। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज ने नई दिल्ली में वाणिज्य उद्योग एवं खाद्य मामलों के मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा के बाद ये जानकारी दी। सीएम ने कहा कि विश्व में अपनी चमक बिखेरेगा मप्र का गेहूं।

नहीं देना होगा टैक्स

उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम ने कहा कि प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट होगा, उस पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा। अभी समितियां और व्यापारी किसान से जो गेहूं खरीदते हैं, इसके लिए उन्हें 100 रुपए की खरीदी पर 1.50 रुपए मंडी टैक्स का देना होता है। यह यानी एक करोड़ रुपए की उपज खरीदी पर 1.50 लाख रुपए मंडी टैक्स लगता है।

गुणवत्ता प्रमाणीकरण की होगी व्यवस्था

गेहूं के वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में इंफ्रा-स्ट्रक्चर और लेब आदि की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को जगह की जरुरत होगी, तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवाएंगे। निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी, तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।

एक लाइसेंस पर प्रदेश में खरीद सकेंगे गेहूं

भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिय निर्यातकों को हर सुविधा दी जाएगी। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं भी गेहूं खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया उपलब्ध है। एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकते हैं। गेहूं की गुणवत्ता और प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में इंफास्ट्राक्चर, लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। एक्सपोर्टर को गेहूं की ग्रेडिंग में आने वाला खर्च राज्य सरकार देगी। गेहूं के निर्यात के लिए रेलवे द्वारा समय से रैक उपलब्ध कराए जाएंगे। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना निर्यात कर सकते हैं।

वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। इस ओर सरकार एवं गेहूं निर्यातक मिल कर प्रयास करें। हमारे संयुक्त प्रयास से मप्र का कनक समान गेहूं विश्व की मंडियों में अपनी चमक बिखेरेगा। मप्र में गेहूं का उत्पादन प्रदेश की ताकत है, इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना है। - शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

सिर्फ 5 प्रतिशत ही राख बचेगी, ग्राउंड वाटर भी नहीं होगा दूषित

भोपाल में लगेगा प्रदेश का पहला एनिमल इंसीनरेटर, हर घंटे 500 किलो जानवरों का होगा दाहसंस्कार

-पांच करोड़ की लागत से आदमपुर में एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा

भोपाल। संवाददाता

मध्य प्रदेश में पहला एनिमल इंसीनरेटर लगेगा, जिससे कई बड़े फायदे होंगे। इसकी हर घंटे 500 किलोग्राम दाहसंस्कार की क्षमता होगी। अभी निगम के पास रोजा 35-40 पशुओं के शव पहुंचते हैं, जिनका वजन करीब तीन टन रहता है। फिलहाल इन शवों को पुरानी तकनीक से यानि जमीन में दफनाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है ग्राउंड वाटर प्रदूषित होने की। ऐसी कई परेशानी को ये एनिमल इंसीनरेटर खत्म कर देगा। निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी की तरफ से एनिमल इंसीनरेटर के लिए वर्कऑर्डर दिया जा चुका है।

ग्राउंड वॉटर के प्रदूषण पर लगेगी रोक- राजधानी भोपाल में 5 करोड़ की लागत से आदमपुर में एक एकड़ जमीन पर एनीमल इंसीनरेटर लगेगा। भोपाल नगर निगम जल्द ही आदमपुर में एनिमल इंसीनरेटर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। ये प्रदेश का पहला एनिमल इंसीनरेटर होगा। मॉडर्न तकनीक के इंसीनरेटर से हर घंटे 500 किग्रा वजन के पशुओं के शवों को जलाया जा सकेगा। दाह संस्कार प्रक्रिया पूरी होने के बाद इंसीनरेटर में केवल 5 फीसदी राख ही बचेगी।

लेवलिंग का काम चल रहा

फिलहाल आदमपुर में लेवलिंग का काम चल रहा है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी का भी इंतजार जारी है। करीब 5 करोड़ की लागत से इसे एक एकड़ में बनाया जाएगा। इसमें बाउंड्री वॉल, शेड, गार्डन एरिया, ऑफिस और राख इकट्ठा करने के लिए एक कमरा भी तैयार किया जाएगा।

ईटीपी भी लगाएंगे

प्लांट से निकलने वाले वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए ईटीपी भी लगाया जाएगा। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के बाद उस पानी को गार्डन में इस्तेमाल किया जाएगा। प्लांट से किसी भी तरह का वेस्ट बाहर नहीं छोड़ा जाएगा।

नया तरीका

मॉडर्न तकनीक का इंसीनरेटर लगने से ग्राउंड वॉटर लेवल के प्रदूषण पर रोक लग जाएगी। इंसीनरेटर में डबल स्क्रबर लगा है, जो गर्म धुएं को ठंडा करेगा और जानवरों की राख के पार्टिकल्स को फिल्टर करेगा। इस धुएं को लगी 30 मीटर ऊंची चिमनी से बाहर निकाला जाएगा।

पुराना तरीका

मौजूदा हाल ही बात करें तो नगर निगम के पास रोज 35 से 40 पशुओं के शव आते हैं, जिन्हें जमीन के नीचे नमक डालकर दफना दिया जाता था। इस तकनीक से बड़े जानवर के शव को नष्ट होने में 60 दिन लगते हैं।

हरदा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना से आसपास के डेढ दर्जन जिले होंगे लाभान्वित

मुरैना, छिंदवाड़ा और हरदा के किसान करेंगे इजरायली तकनीक से खेती!

-अब हरदा में भी बनेगा इजरायल सरकार का सेंटर फॉर एक्सीलेंस

-नवाचारः इजरायल और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुए एमओयू

भोपाल। बागवानी फसलों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश में मध्य प्रदेश सरकार जुट गई है। भारत-इजरायल कृषि परियोजना के तहत यहां बागवानी के दो प्रोजेक्ट तैयार होंगे। छिंदवाड़ा में संतरा और मुरैना में सब्जियों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। इससे यहां के किसानों को फायदा होगा। वे आधुनिक तरीके से कम जगह में ज्यादा और अच्छा उत्पादन लेने की विधि सीख पाएंगे। इस संबंध में पिछले दिनों इजराइल के काउंसलेट जनरल कोबी शोशानी ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि इजराइल का भारत में 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में से दो को मध्य प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार के इन प्रयासों से ना सिर्फ प्रदेश में उन्नत तकनीक की खेती होगी बल्कि इसका फायदा किसानों को होगा।

उन्नत कृषि की इजरायली तकनीक की सेंटर फॉर एक्सीलेंस को लेकर इजरायल एवं मध्य प्रदेश सरकार के बीच हुए एमओयू के आधार पर चिन्हित स्थानों में परिवर्तन करते हुए मुरैना, छिंदवाड़ा के साथ हरदा को भी सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने का प्रस्ताव देते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने वर्चुअली इजरायली दूतावास के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों से चर्चा की।

खेती बनेगी लाभ का धंधा

कृषि मंत्री ने कहा कि हरदा को इजरायली खेती किसानी के तौर-तरीकों पर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाता है तो मध्यप्रदेश के दो दर्जन से अधिक जिलों के किसानों को इजरायली तकनीक का लाभ मिल सकेगा जिससे वे खेती को घाटे की बजाए लाभ का धंधा बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

इजराइल करेगा सहयोग

इजराइल में एक पखवाड़े के विशेष पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश के कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारी लाभान्वित किए जाएंगे। शोशानी ने मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में हुए विकास की सराहना की। उन्होंने कृषि सहित सिंचाई, उद्योग, व्यापार-वाणिज्य क्षेत्रों में इजराइल द्वारा पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।

हरदा में सेंटर की स्थापना से हरदा ,नर्मदापुरम, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ जिलों में इजरायली तकनीक से उन्नत कृषि की संभावनाएं हैं। मप्र का किसान आत्मनिर्भर मप्र की ओर बढ़ सकेगा।
कमल पटेल, कृषि मंत्री

खरीफ-रबी 2020-21 के बीमा क्लेम का पैसा आया, मिला नहीं

सहकारी बैंकों के सस्पेंस एकाउंट में किसानों का 600 करोड़ रुपए अटका

एनईएफटी फेल होने पर दो दिन में रिटर्न होता है, पर हुआ नहीं

भोपाल। संवाददाता

मध्यप्रदेश के साढ़े तीन लाख किसानों को खरीफ 2020 और रबी 2020-21 के 600 करोड़ रुपए बंटने थे, लेकिन ये पैसा 25 जिला सहकारी बैंकों के सस्पेंस एकाउंट (डीएमआर) में एक महीने से पड़ा हुआ है। इसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के जरिए किसानों के खातों में ट्रांसफर करना था, लेकिन एनईएफटी फेल होने के कारण ये अटक गया।

जबकि आरबीआई का नियम है कि एनईएफटी फेल होने के बाद एक या दो दिन में पैसा मूल खाते में लौटना चाहिए, लेकिन इस मामले में एक महीने से बैंकों ने पैसा रोक कर रखा है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह वैस को जब इसकी जानकारी मिली तो राशि इंश्योरेंस कंपनी को लौटाना शुरू की गई, ताकि किसानों तक पैसा दोबारा पहुंच सके।

क्लेम के सवा सौ करोड़ लौटाए

बैंकों ने 4 लाख 5 हजार 152 किसानों का 715 करोड़ 44 लाख रुपए रोक रखा था। हड़कंप मचा तो हाल ही में 125 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इश्योरेंस कापोर्रेशन को लौटा दिए। गौरतलब है कि 12 फरवरी को सिंगल क्लिक पर 49 लाख क्लेम के 7618 करोड़ सरकार ने किसानों को ट्रांसफर किए थे। इसमें से सहकारी बैंक में 18 लाख 83 हजार 523 किसानों के क्लेम का 3240 करोड़ गया। इसी में से 600 करोड़ बैंकों ने सस्पेंस एकाउंट में डाल रखा है।

कृषि संचालक ने लिखा पत्र

कृषि संचालक प्रीति मैथिल नायक ने 12 मार्च को अपैक्स बैंक के एमडी और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के स्टेट को-आर्डिनेटर को पत्र लिखा और कहा कि किसानों के सही बैंक एकाउंट नंबर बीमा कंपनी को उपलब्ध कराएं। ताकि क्लेम का भुगतान किया जा सके। इसके बाद ही आनन-फानन में सहकारी बैंकों ने क्लेम निपटाने का काम शुरू किया।

एनईएफटी फेल होने के वजह से पैसा रुका था। सोसायटी ने गलत जानकारियां भेजी। संख्या ज्यादा होने की वजह से भी कुछ दिक्कतें थी। जल्द सब ठीक किया जाएगा। एक-दो दिन में पूरा पैसा खातों से निकल जाएगा।
- पीएस तिवारी, एमडी, अपैक्स बैंक

गेहूं के दाम जाएंगे चार हजार के पार

अब 4000 रुपए तक महंगी होगी रोटी

इंदौर। संवाददाता

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच खाद्य पदार्थों की महंगाई आसमान छू रही है। अनाज भी इससे अछूता नहीं है। स्थानीय मंडी में गेहूं के दामों में जोरदार उछाल दर्ज किया जा रहा है। छावनी मंडी में गेहूं के दामों में 100 रुपए की तेजी नजर आई। दरअसल यूक्रेन गेहूं और सूरजमुखी उत्पादों का बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी रहा है। युद्ध के कारण यूक्रेन से निर्यात रुक गया है। इसके बाद विदेशों से भारतीय गेहूं की भी इस साल अच्छी मांग नजर आ रही है। नए गेहूं की आवक शुरू होने के साथ ही निर्यात भी शुरू हो गया है। इससे दामों में उछाल है। आसार हैं कि इस साल अच्छी क्वालिटी का रोटी वाला गेहूं जो आमतौर पर घरेलू उपभोक्ता वार्षिक संग्रहण करता है। बीते वर्ष के मुकाबले 500 से 800 रुपए प्रति क्विंटल महंगा मिलेगा। अब सरकार की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट की घोषणा गेहूं की महंगाई को और बल देती दिख रही है।

अप्रैल से बढ़ेगी मांग| इंदौर मंडी के व्यापारी मान रहे हैं कि निर्यात के दबाव और तेजी की उम्मीद में किसान अभी अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं मंडी में नहीं ला रहा है। अप्रैल से वार्षिक संग्रहण के लिए गेहूं की मांग शुरू हो जाएगी। चालने वालों को अभी गेहूं मिल ही नहीं रहा। ऐसे में उनका सीजन बिगड़ता दिख रहा है।

3000 क्विंटल की उम्मीद| सामान्य क्वालिटी का गेहूं इस वर्ष 2700 से 3000 रुपए क्विंटल बिकने की उम्मीद है। इसी तरह रोटी वाला बेस्ट चंदौसी क्वालिटी के गेहूं के दाम इस साल 4000 रुपए क्विंटल तक पहुंचेंगे। कारोबारियों के अनुसार 15 दिनों से गेहूं में निर्यात की मांग देखी जा रही है। पहले इंदौर से गेहूं कांडला बंदरगाह भेजा जा रहा था।

लॉन्च किया ड्रोन ऑपरेशन प्लेटफार्म स्काईडेक

जियो की कंपनी बदलेगी खेती की सूरत

भोपाल। संवाददाता

एस्टेरिया एयरोस्पेस जियो प्लेटफार्म लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो भारत में ड्रोन बनाती है। वहीं एस्टेरिया कंपनी ने अपना एंड-टू-एंड ड्रोन ऑपरेशन प्लेटफार्म लॉन्च किया है। इस ड्रोन ऑपरेशन प्लेटफार्म को क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म स्काईडेक दिया गया है। मंच कृषि, सर्वेक्षण, निगरानी, औद्योगिक निरीक्षण और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए एंड-टू-एंड ड्रोन समाधान प्रदान करता है। स्काईडेक एक केंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली है जो ड्रोन की उड़ान के विभिन्न मापदंडों और संबंधित डेटा को रिकॉर्ड करती है और इसे विशेष रूप से विकसित डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करती है। प्लेटफार्म में ड्रोन डेटा प्रोसेसिंग, डेटा के विजुअलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा डेटा के विश्लेषण की सुविधा भी है। इसके अलावा ड्रोन फ्लाइट शेड्यूलिंग से लेकर ड्रोन फ्लीट मैनेजमेंट भी इस सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा सकता है।

एस्टेरिया पहले से ही भारत में अग्रणी ड्रोन निर्माताओं में से एक है। स्काईडेक के लॉन्च के साथ, हम एक एकीकृत प्लेटफार्म के माध्यम से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और परिचालन समाधान जैसी सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं।
नील मेहता, सह-संस्थापक और निदेशक, एस्टेरिया एयरोस्पेस

फसल के रखरखाव में उपयोगी

स्काईडेक के एंड-टू-एंड समाधान कृषि क्षेत्र के परिदृश्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। इसका उपयोग फसल की विशेषताओं को सटीक रूप से मापने, कीटों, उर्वरकों, पानी आदि का निरीक्षण करने के लिए किया जा सकता है। निर्माण और खनन उद्योगों के लिए, स्काईडेक प्रगति की निगरानी और सटीक इन्वेंट्री रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए साइट सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन-आधारित हवाई डेटा का उपयोग करता है। तेल और गैस, दूरसंचार और बिजली जैसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्षेत्रों के लिए, स्काईडेक रखरखाव, जोखिमों की पहचान और परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग के लिए संपत्तियों को डिजिटाइज और मॉनिटर करने के लिए ड्रोन की शक्ति का उपयोग करता है। स्काईडेक विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे स्वामित्व योजनाओं, स्मार्ट शहरों, कृषि-स्टैक और अन्य विकास परियोजनाओं में ड्रोन के बेड़े के सफल कार्यावयन में भी मदद कर सकता है।

गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय

मंत्रीद्वय बिसाहूलाल-भदौरिया ने उपार्जन पर किया मंथन

समर्थन पर किसानों का एक एक दाना खरीदेगी सरकार

भोपाल। संवाददाता

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की उपज का एक एक दाना खरीदेगी। इसके लिए शासन द्वारा पंजीयन से लेकर भुगतान तक की पारदर्शी व्यवस्था की गई है। मंत्री बिसाहूलाल सिंह और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने किसानों से समर्थन मूल्य पर रबी विपणन की खरीदी पर मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो विगत वर्ष से 40 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। प्रदेश सरकार 28 मार्च से गेहूं उपार्जन प्रारंभ करने जा रही है। इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में 28 मार्च से 10 मई, 2022 तक एवं नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर, भोपाल एवं चम्बल संभाग के जिलों में 4 अप्रैल से 16 मई तक खरीदी की जाएगी। मंत्री सिंह ने बताया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी 4663 उपार्जन केन्द्रों पर खरीदी की जाएगी। इसके अतिरिक्त सायलो मालिकों द्वारा संचालित उपार्जन केन्द्र पर अलग से खरीदी होगी, जो 4663 केन्द्रों के अतिरिक्त होंगे।

मंत्रीद्वय ने बताया कि वास्तविक किसानों का ही पंजीयन हो सके, इसके लिए शासन द्वारा पंजीयन करने के लिए आधार नम्बर आधारित बायोमेट्रिक/ ओटीपी सत्यापन के आधार पर पंजीयन की व्यवस्था की गई थी। इसमें कुल पंजीयन का 41 प्रतिशत बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा पंजीयन किया गया। इसके तहत ऐसे शारीरिक रूप से अक्षम एवं वृद्ध कृषक, जिनके पास आधार नम्बर नहीं था, उन्हें नामिनी के माध्यम से पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इस सुविधा का लाभ 28 हजार 298 कृषकों द्वारा लिया गया। गेहूं उपार्जन के लिये 19 लाख 81 हजार किसानों ने पंजीयन कराया, जो विगत वर्ष का 80 प्रतिशत है। इसमें कुल रकबा 42.24 लाख हेक्टेयर है, जो विगत वर्ष से 84 प्रतिशत अधिक है।

किसान की पसंद का होगा केन्द्र

किसानों को गर्मी बेचने के लिए एसएमएस की प्रतीक्षा नहीं करना होगी। अब वे स्वयं स्लॉट बुकिंग कर अपनी पसंद के उपार्जन केन्द्र और विक्रय के लिए दिनांक तथा समय का चयन कर सकेंगे। उपार्जन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से दोपहर एक बजे तक एवं 2 बजे से 6 बजे तक किया जाएगा। गर्मी विक्रय के लिए स्लॉट की वैधता 3 कार्य दिवस के लिए होगी। स्लॉट बुकिंग करने के पश्चात कृषक उपार्जन केन्द्र का नाम, विक्रय योग्य मात्रा एवं विक्रय के दिनांक की जानकारी का प्रिंट निकाल सकेंगे।

किसानो को उनकी उपज का भुगतान उनके आधार लिंक खाते में करने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना को समाप्त किया जा सके। इसके लिए किसान को बैंक शाखा में जाकर खाते को आधार से लिंक कराना होगा। किसान द्वारा एफक्यू मापदण्ड का गेहूं विक्रय के लिए लाया जाता है, तो उसकी साफ-सफाई की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षण में गेहूं नॉन एफक्यू पाया जाएगा, तो किसानों को अपना गेहूं साफ कराना होगा।

बिसाहुलाल सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

उपार्जित गेहूं के भंडारण के लिए 84 लाख मीट्रिक टन के लिये स्थान रिक्त है। आगामी माह में पीडीएस एवं अन्य माध्यम से स्कंध के उठाव से 34 लाख मीट्रिक टन क्षमता रिक्त होगी। 58 लाख मीट्रिक टन के नवीन गोदाम निजी क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं। 4 लाख मीट्रिक टन के सायलो भी बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार कुल 180 लाख मीट्रिक टन क्षमता भंडार के लिए उपलब्ध है। विभाग द्वारा उपार्जन केन्द्र पर गेहूं की सफाई की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री

सरसों बेचने के लिए सात गुना अधिक पंजीयन

मुरैना में गेहूं बेचने वाले किसान आठ गुना कम

मुरैना। संवाददाता

समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद इसी माह से शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बार मुरैना जिले के किसान सरकार को गेहूं बेचने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। यह स्थिति समर्थन मूल्य के लिए हो रहे पंजीयन में सामने आई है। बीते साल से आठ गुना से भी कम किसानों ने पंजीयन कराया है। दूसरी ओर समर्थन मूल्य पर सरसों को बेचने के लिए किसानों ने जमकर पंजीयन कराए हैं। बीते साल गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल था, जो इस बार 40 रुपए बढ़कर 2015 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। बीते साल समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 38136 किसानों ने पंजीयन करवाया। इसकी तुलना में इस साल पंजीयन कराने वालों की संख्या 4946 पर रुक गई है।

सरसों के पंजीयन बंपर

पिछले साल समर्थन मूल्य पर सरसों बेचने के लिए 4463 किसानों ने पंजीयन करवाया था। उस समय पिछले साल सरसों का समर्थन मूल्य 4400 रुपए था, जो इस बार बढ़कर 5050 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य दाम बढ़ाया तो पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या में भी बंपर बढ़ोतरी हुई है। समर्थन मूल्य पर सरसों बेचने के लिए 35993 किसान पंजीयन करा चुके हैं। यानी पिछले साल के मुकाबले सात गुना से ज्यादा। हालांकि समर्थन मूल्य पर सरसों के बिकने की संभावना भी न के बराबर है, क्योंकि बाजार में सरसों का दाम 7000 रुपए क्विंटल के आसपास चल रहा है।

283 किसानों का बाजरा वापिस

खरीफ सीजन में सरकार ने 2250 रुपए क्विंटल के समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीदी की थी, जिसमें मुरैना जिले के किसान बेहद परेशान हुए। सरकार को बाजरा बेचने के लिए 39 हजार 102 किसानों ने बाजरा खरीदी के लिए पंजीयन करवाया, जिसमें से मात्र 283 किसानों से 2109 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया। इन 283 किसानों का बाजरा भी खरीदी के डेढ़ महीने बाद वापिस कर दिया गया, यानी जिले के एक भी किसान का बाजरा समर्थन मूल्य पर नहीं बिका।

इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या कम रही है। सरसों का भाव अच्छा होने से इस बार अधिकतर किसानों ने सरसों की खेती की है, यह भी एक कारण रहा है। खरीफ सीजन में बाजरा की गुणवत्ता सही नहीं थी इसलिए समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया, इसका असर कितना पड़ा है यह नहीं बता सकते।

बीएस तोमर, जिला आपूर्ति नियंत्रक, मुरैना

इंदौर में ग्रेनएक्स इंडिया में प्रदर्शित हुईं आधुनिक मशीनें, राज्यपाल मंगू भाई पटेल बोले

मोटे अनाजों का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना बढ़ा

इंदौर। संवाददाता

ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा दाल, अनाज एवं अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अत्याधुनिक मशीनों की प्रदर्शनी ग्रेनएक्स इंडिया-2022 का आयोजन किया गया है। 24 से 26 मार्च तक इंदौर में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक महेंद्र हार्डिया, इंदौर के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, मध्य प्रदेश के अनाज संघ के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल एवं अकोला के दालमिल के अध्यक्ष मेश सुरेखा व कई जिलाधिकारी भी मौजूद थे। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं। मोटे अनाजों का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना बढ़ा है। इस आयोजन में ऐसी नई मशीनें प्रदर्शित की गई हैं, जिनसे गुणवत्तायुक्त दालें और उच्च स्तरीय प्रोडक्ट मिलेंगे। उद्योग संचालकों और उपभोक्ताओं दोनों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि दाल मिल एवं इसी तरह के अन्य उद्योग संचालक इस प्रदर्शनी के माध्यम से वे अपने देश की ही नहीं, बल्कि विदेशी कंपनियों की मशीनें भी एक ही स्थान पर देख पा रहे हैं। इससे उन्हें परेशानी भी कम होगी। दाल मिलों व उद्योगों का यह सराहनीय प्रयास है।

सौ कंपनियों ने लिया भाग- ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि दाल, सोयाबीन, चना, चावल, गेहूं, मसाला सहित अनाज उद्योग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और आधुनिकीकरण संबंधी सभी जानकारी को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें देश-विदेश की 100 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया है। दाल मिलिंग, पैकेजिंग, क्लीनर ग्रेडर से लेकर मैग्नेटस बनाने वाली कंपनियां तक इनमें शामिल हैं।

उत्पादों का दिया लाइव डेमो

प्रदर्शनी में चीन, जापान, तुर्की सहित अन्य देशों की अनेक नामी कंपनियों के साथ भारत के चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, राजकोट, सोनीपत, फरीदाबाद, दिल्ली सहित अनेक शहरों के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की मशीन निर्माता कंपनियां अपनी अत्याधुनिक मशीनों (उत्पादों) का लाइव डेमो दिया। अनाज उद्योग की बढ़ती जरूरतों के लिए व्यापार का विस्तार करने और बाजार का पता लगाने के लिए ग्रेनएक्स इंडिया एक बड़े मंच के रूप में सभी के सामने है।

14 राज्यों की व्यापारी आए

इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों से दाल मिल व्यापारी एवं अनाज व्यापारी शामिल हुए। दाल मिलर्स/फ्लोअर मिल एवं अन्य खाद्य प्रसंस्करणकर्ता व्यापारी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक प्रदर्शनी में जानकारी हासिल किए।

वैज्ञानिक तरीके से टमाटर का प्रसंस्करण जरूरी

डॉ. शालिनी चक्रवर्ती
वरिष्ठ वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान
कृषि विज्ञान केंद्र, राजगढ़

टमाटर एक अति पौष्टिक फल एवं सब्जी है। टमाटर में विटामिन ए, बी, सी, कैल्सियम और लौहा पाया जाता है। मौसम में जब टमाटर काफी मात्रा में उपलब्ध होता है, उस समय उनकी बड़ी मात्रा सस्ती बिकती है। अत्यधिक उत्पादन होने पर मूल्य कम होता है, जबकि आवक कम होने पर इसका मूल्य बढ़ जाता है। टमाटर एक बहुत जल्दी खराब होने वाली फसल है। कुल उत्पादन का लगभग 25-30 प्रतिशत सड़-गलकर बेकार हो जाता है, क्योंकि इन्हें पेड़ से तोड़ने के बाद अधिक समय तक रखा नहीं जा सकता है।

जब बाजार में इसका उचित मूल्य न मिले तब इसका प्रसंस्करण कर भंडारण करें और उत्पाद को बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमाएं। पूरे वर्ष टमाटर का उपयोग करने के लिए इस को कई प्रकार से प्रसंस्करित किया जा सकता है। टमाटर का सबसे अच्छा प्रसंस्करण सॉस बनाकर रख सकते हैं। यदि इन्हें सावधानी से वैज्ञानिक ढंग से बनाया जाए तो ये अधिक दिनों तक टिक सकते हैं। यद्यपि बड़े कारखानों में आजकल टमाटर के उत्पादों का काफी मात्रा में उत्पादन होता है। लेकिन ये इतने मंहगे मिलते हैं कि मध्य एवं कम आमदनी वाले परिवारों में इसका उपयोग कर पाना कठिन हो जाता है। इस दृष्टिकोण से यदि टमाटर से विभिन्न उत्पाद बनाने की विधियों को सीखकर इन्हें घर पर बनाए जाएं तो ये पदार्थ बहुत कम लागत में तैयार हो सकते हैं।

टमाटर का सॉस

लगभग 10 किलो पके टमाटर से सॉस बनाने के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता रहती है। अधिक टमाटर होने पर इसी अनुपात में सामग्री मिलाएं।

सामग्री:

पूर्णत: पके हुए लाल टमाटर -10 किलो, लहसुन की छिली हुई कलियां-20 ग्राम, अदरक (अच्छी तरह साफ कर)- 20 ग्राम, सूखी लाल मिर्ची-10 ग्राम (स्वादानुसार)
किशमिश (सुनहरी रंग की)-100 ग्राम, सिरका-250 मिली, काला नमक-4 चम्मच (स्वादानुसार), शक्कर-100 ग्राम (स्वादानुसार), सोडियम बेंजोएट- 2.5 ग्राम।

विधि:

पूर्णत: पके हुए टमाटर ले इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें। डंठल आदि निकाल कर अलग कर दें। टमाटर को पानी से अच्छी साफ कर पानी को अच्छी तरह से निकल दें। अच्छी तरह साफ करने के बाद इन्हें काट लें, काटते समय गला हुआ या दागी भाग निकाल कर अलग कर दें। कटे हुए टमाटर को बड़े बर्तन या कुकर में डाल दें। अच्छी तरह से कटे हुए अदरक, लहसुन, किशमिश और सूखी मिर्ची के टुकड़े मिला दें। फिर ऊपर से सिरका और शक्कर मिला दें। धीमी आंच पर अच्छी तरह से मिलाते हुए लगभग 10 मिनट तक गरम करें। अतिरिक्त पानी न मिलाएं। पुन: परीक्षण करें, टमाटर अब नरम होने लगेंगे। चम्मच से अच्छी तरह से लगभग आधा घंटे चलाते रहें। अच्छी तरह से पके हुए हल्के गरम गूदे को घोटनी या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से महीन कर लें। महीन गूदे को मध्यम आकार की छलनी से चम्मच से चलाते हुए अलग बर्तन में छान लें। छना हुआ गूदा सॉस बनाने के लिए तैयार है। इसे अब हल्की लौ पर 5-6 मिनट हिलाते हुये गरम करें। स्वाद के अनुसार, शक्कर, नमक आदि मिलाये। लगभग 20 मिनट गाढ़ा होते तक चम्मच से हिलाते हुये उबालें। गाढ़ेपन के परीक्षण के लिए एक चम्मच सॉस प्लेट पर डाल दें। इसके किनारे पर पानी नहीं दिखना चाहिए। आवश्यकतानुसार गाढ़ा कर सकते हैं। जार या कांच की बोटल को उबालकर, सुखाकर जीवाणु रहित कर लें। सोडियम बेंजोएट को 4 चम्मच गरम पानी में अच्छी तरह घोलकर, गरम सॉस में हिलाते हुए मिला दें। अब इसे जीवाणु रहित जार या बोटल में डाल, ध्यान रहे ऊपर से लगभग आधा इंच खाली रखें। अच्छी तरह से ढक्कन लगाकर बंद कर कमरे के तापमान पर पूरे दिन ठंडा होने दें। पूरा ठंडा होने पर फ्रीज में रखकर ठंडा करें। अब आपका सॉस 1-2 दिन में खाने के लिए तैयार है।

सावधानियां

टमाटर को अच्छी तरह से साफ करें, सड़े हुए भाग को निकाल दें। धीमी आंच/ लौ पर अच्छी तरह हिलाते हुए उबाले, जिससे बर्तन की तली में न चिपके या जले। गूदा महीन बनना चाहिए। उपयोग में आने वाले बर्तन, छलनी, जार या बोटल को उबालकर, सुखाकर जीवाणु रहित कर लें। इनमें नमी नहीं रहना चाहिए। भंडारण के लिए वायुरोधी जार या बोटल का ही प्रयोग करना चाहिए।

टमाटर का रस

सामग्री: टमाटर का रस-1 लीटर, चीनी-10 ग्राम, नमक-5 ग्राम, सिट्रिक अम्ल-1 ग्राम, सोडियम बेंजोएट (परिक्षक)- 1/4 चम्मच। विधि: टमाटर का रस बनाने के लिए पके हुए पूरे लाल टमाटर चुने। टमाटर को धोएं, डंठल आदि हटा दे तथा छतिग्रस्त और रंगीन भाग काटकर अलग कर दें। टमाटरों को चार टुकड़ों में काटकर भगोने में डालकर उबाले और उबालते समय बीच-बीच में कुचलते रहें। लगभग 10 मिनट तथा मुलायम होने तक गमर् करें। फिर टमाटरों को स्टील की छन्नी से छानकर, छिलका एवं बीच अलग करें। रस में नमक, चीनी एवं सिट्रिक अम्ल मिलाएं। रस को एक बार पुन: खौलने तक उबालें। आंच से उतारने के पश्चात सोडियम बेंजोएट को रस में मिलाए एवं गर्म रस को कांच की निर्जर्मिकृत नमी रहित स्थान पर भंडारित करें। बोतलों में भरकर ढक्कन लगा दें।

टमाटर की प्यूरी

सामग्री: टमाटर का रस-1 किग्रा, सोडियम बेंजोएट (परिरक्षक)-1/4 चम्मच। **विधि:** पहले बताई गई विधि से लाल टमाटर का रस निकालें। फिर रस गर्मकर गाढ़ा करें जब तक की ये अपनी मूल मात्रा का एक तिहाई या एक चौथाई ना हो जाए। रस को गाढ़ा करने के लिए या तो खुले कुकर या भगोने में पकाया जाता है। पकाते समय टमाटर के रस में मक्खन या खाद्य तेल मिला देना चाहिए, जिससे की रस बर्तन की तली में ना चिपके। टमाटर की प्यूरी पककर तैयार हो गई है या नहीं यह निर्धारण करने के लिए या तो रिफ्रेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है या इस के लिए गाढ़े किए हुए टमाटर की प्यूरी को प्लेट पर चम्मच की सहायता से डालते हैं। यदि प्लेट पर डाली गई प्यूरी से पानी नहीं छूट रहा है तो इसका अर्थ है की प्यूरी अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच गई है। अब पदार्थ को आग से उतारे एवं सोडियम बेंजोएट को अच्छी तरह मिला दें। गर्म प्यूरी को निर्जर्मिकृत कांच के जार, बोतल में भरकर ढक्कन लगा दें। सूखे एवं नमी रहित स्थान पर भंडारित करें।

4. टमाटर का पाउडर

सामग्री: लाल पके टमाटर। विधि: सर्वप्रथम टमाटर को अच्छी प्रकार से धो लें। टमाटर के डंठल वाले भाग को अलग निकाल दें। अब टमाटर के पतले चिप्सनुमा टुकड़े काट लें। शुष्कक का तापमान 125 डिग्री सेन्टीग्रेट पर सेट करके अलग-अलग ट्रे पर एक परत में टमाटर के टुकड़े को बिछाएं। 12 से 16 घंटे के बीच यह टमाटर पूरी तरह से सूख जाएंगे। अब इन सूखे टुकड़ें को पलवराइजर में डाल कर पीसे। पीसे हुए पाउडर को थैलियों में सीलबंद कर सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।

बेमौसम उपयोग के लिए ऑवला परिरक्षण

डॉ. रीता मिश्रा एवं डॉ.वायडी मिश्रा
कृषि विज्ञान केंद्र, मुरैना एवं निदेशालय
विस्तार सेवाएं, रा.वि.कृ.वि.ग्वालियर

आंवले का फल बहुत गुणकारी होता है। इसमें आयरन और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। परन्तु ऑवले के कुल उत्पादन का अधिकांश भाग भंडारण के समय सड़-गलकर बेकार हो जाता है। यदि इसे परिरक्षत करके रख लें तो भंडारण के समय होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। साथ ही परिरक्षत पदार्थो की बाजार में बिक्री कर लाभ कमाया जा सकता है। इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।

आंवले का परिरक्षण विविध प्रकार से किया जा सकता हे। जैसे ऑवले का मुरब्बा, अचार, चटनी, चूर्ण, लड्डू आदि।

100 ग्राम ऑवले में उपस्थित पोषक तत्व

कार्बोहइडेट	13 ग्राम
कैल्शियम	50 ग्राम
फास्फोरस	20 ग्राम
आयरन	1 मिग्रा
विटामिन	600 मिग्रा

ऑवले के पौष्टिक गुण: यह सर्दी,जुकाम तथा अन्य संक्रमण रोंगों से लडने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। यह पायरिया से बचाव में, घाव के भरने में तथा हड्डियों व दॉतों को मजबूती प्रदान करता है। यह भूख बढ़ाता है।

मूल्यवर्धित उत्पाद

आंवले का मुरब्बा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आंवले का मुरब्बा यदि गर्मी में रोजाना खाएं तो यह बहुत तरावट देने वाला और दिमाग को ताकत देने वाला होता है। मुरब्बे के लिए आंवले अच्छी तरह से पके होना चाहिए और उनमें कोई दाग नहीं होना चाहिए। कांच के सूखे कंटेनर में ये मुरब्बा भरकर रख लीजिए।

मुरब्बा बनाने की विधि

आंवले की चाशनी को अच्छी तरह पका लीजिए नहीं तो मुरब्बा जल्दी खराब हो सकता है। यदि कभी चाशनी पतली हो रही हो तो आप फिर से पका कर भी गाढ़ी कर सकते हैं। आंवले को कांटे की सहायता से अच्छी तरह गोद लीजिए। मुरब्बा नरम बनेगा और चाशनी भी जल्दी ही उसके अन्दर चली जाएगी।

सावधानी: पानी में आंवले देर तक न पकाएं अन्यथा वे टूट जाएंगे।

ऑवले का मुरब्बा: स्वस्थ व पूर्ण विकसित आंवलों का चयन करना। साफ पानी से धोना। स्टेनलैस स्टील के कांटों से आंवलों को गोदना। आंवलों को 3-4 प्रतिशत चूने के पानी मे 10-12 घण्टे के लिए रखना। आंवलों को साफ पानी से धोना। एक तार की चाश्नी बनाना। सिट्रिक एसिड डालना। चाश्नी छानना: आंवलों को गरम चाश्नी में 24 घंटे के लिए छोड़ना। आंवलों को निकालकर चाश्नी को एक तार की चाश्नी बनाना। आंवलों को चाश्नी में डालना। 8-10 दिन बाद चाश्नी को फिर पकाना। चाश्नी सहित आंवलों का भंडारण करना।

ऑवला कैंडी: स्वस्थ व पूर्ण विकसित आंवलों का चयन करना। साफ पानी से धोना। स्टेनलैस स्टील के कांटों से आंवलों को गोदना। आंवलों को 3-4 प्रतिशत चूने के पानी मे 24 घंटे के लिए रखना। आंवलों को साफ पानी से धोना। 5 से 10 मिनट तक उबालना। गुठली निकालकर फांके अलग करना। आंवले के टुकड़ों/ फांकों को चीनी की परतों के बीच 3 दिन तक रखना। आंवलों के टुकड़ों को निकालकर तीन तार की चाश्नी बनाना। सिट्रिक एसिड डालना।

चाश्नी: आंवलों के टुकड़ों को चाश्नी में एक हफ्ते के लिए छोड़ना। आंवलों को टुकड़ों को चाश्नी से निकालकर छायादार स्थान में सुखाना। या ओवन में 80 डिग्री तापमान पर 5-6 घंटे तक सुखाना। आंवलों के टुकड़ों के ऊपर पिसी चीनी व पिसी इलायची छिड़कना।

आंवला कैंडी: पॉलीथीन की थैलियों में भंडारण करना।

भारत को वनों के संरक्षण के लिए क्या फिर पड़ेगी चिपको आंदोलन की जरूरत

26 मार्च चिपको आंदोलन की वर्षगांठ। चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई। यह भट्ट और दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने इलाहाबाद स्थित स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी साइमंड्स को 14 ऐश के पेड़ काटने से रोका। यह कार्य 24 अप्रैल को हुआ और दिसंबर में ग्रामीणों ने गोपेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर फाटा-रामपुर के जंगलों में साइमंड्स के एजेंटों को फिर से पेड़ों को काटने से रोक दिया। चिपको एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ 'चिपके रहने' या 'गले लगाने' से है। यह उत्तर भारत की पहाड़ियों में गरीब, गांव की महिलाओं के वनों को बचाने की छवियों को उजागर करता है, जो पेड़ों को ठेकेदारों की कुल्हाड़ियों से काटने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ पेड़ों को गले लगाती है, जिससे उनकी जान को भी खतरा होता है। लेकिन चिपको की बहुआयामी पहचान के परिणामस्वरूप अलग-अलग लोगों के लिए इसका अर्थ अलग-अलग हो गया है। कुछ के लिए, यह गरीबों का एक असाधारण संरक्षण आंदोलन है। वहीं दूसरों के लिए, यह अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए एक स्थानीय लोगों का आंदोलन है, जिसे पहले एक औपनिवेशिक शक्ति द्वारा और फिर भारत की स्वतंत्र सरकार द्वारा छीन लिया गया। अंत में यह महिलाओं का एक आंदोलन बन कर उभरा जो अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ काटने वालों को यह संदेश देना कि पेड़ों को काटने से पहले हमारे शरीर को कटना होगा। वास्तव में एक महिला आंदोलन के रूप में, इसने भारत में और कुछ हद तक दुनिया भर में पर्यावरण-नारीवाद को प्रेरित किया। 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ ब्लॉक के रेनी गांव के पास पेंग मुरेंडा जंगल में पेड़ों को काटने के लिए चुना, यह इलाका 1970 की भीषण अलकनंदा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित था। ऋषिकेश के एक ठेकेदार जगमोहन भल्ला को 4.7 लाख रुपए में 680 हेक्टेयर से अधिक जंगल की नीलामी की गई। लेकिन रेनी गांव की महिलाओं ने 26 मार्च 1974 को ठेकेदार के मजदूरों को बाहर निकाल दिया। यह चिपको आंदोलन के लिए एक अहम मोड़ था, क्योंकि इसमें पहली बार महिलाओं द्वारा पहल की गई, खासकर जब उनके पुरुष आसपास नहीं थे। रेनी की घटना ने राज्य सरकार को दिल्ली के वनस्पतिशास्त्री वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति गठित करने के लिए प्रेरित किया और जिसके सदस्यों में सरकारी अधिकारी थे। इसमें स्थानीय विधायक, सीपीआई के गोविंद सिंह नेगी, भट्ट तथा जोशीमठ के ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह रावत शामिल थे। समिति की रिपोर्ट दो साल बाद प्रस्तुत की गई, जिसके कारण रेनी में अलकनंदा के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगभग 1,200 वर्ग किमी के हिस्से में व्यावसायिक वानिकी पर 10 साल का प्रतिबंध लगा। 1985 में प्रतिबंध को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। चिपको को एक और प्रतिक्रिया निजी ठेकेदारों से सभी प्रकार के पेड़ों को काटे जाने से संबंधित अधिकार लेने के लिए 1975 में एक राज्य के स्वामित्व वाली वन निगम का गठन किया था। लेकिन वन निगम के खिलाफ चलने वाले कई आंदोलनों को उस समय निशाना बनाया गया था। 1974 में 25 जुलाई को एक संघर्ष शुरू किया गया था जो अक्टूबर में अपने चरम पर पहुंच गया। इसी के चलते उत्तरकाशी के पास व्याली वन क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को काटे जाने से रोका गया। कुमाऊं में चिपको ने 1974 में नैनीताल में नैना देवी मेले में अपनी शुरुआत की और फिर नैनीताल, रामनगर और कोटद्वार सहित कई स्थानों पर वन नीलामी को अवरुद्ध करने के लिए यह आगे बढ़ा। 1977 में तवाघाट में बड़े भूस्खलन के बाद कुमाऊं में आंदोलन ने गति पकड़ी।

कागजों तक सीमित रह गया प्रतिबंध, 2100 रुपए क्विंटल तक बिक रहा, पशुपालक परेशान

कालाबाजारी से बढ़ा मुरैना में भूसे का संकट

अवधेष डंडोतिया, मुरैना।

मुरैना जिले में भूसे का संकट दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। भूसे के दाम इतने बढ़ गए हैं कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के पशुपालकों को मवेशियों के लिए चारा भी नहीं मिल रहा। ऐसे में मजबूरी में लोग अपनी मवेशियों को बेसहारा छोड़ना पड़ रहा है। यह संकट भूसे के अवैध परिवहन के कारण बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने भूसे को जिले से बाहर परिवहन करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन यह प्रतिबंध कागजों तक सीमित रह गया है। भूसे का संकट तो अगस्त महीने में आई भीषण बाढ़ के बाद से ही होने लगा था, लेकिन इस संकट को राजस्थान व उत्तर प्रदेश में होने वाली भूसे की सप्लाई ने और बढ़ा दिया। राजस्थान व उत्तर प्रदेश में ईंट की चिमनियों में भूसे का उपयोग होता है। यह चिमनी मालिक बीते साल तक 700 से 750 रुपए क्विंटल में भूसा खरीदते थे, जिसके दाम इस बार 1500 से 1600 रुपए क्विंटल तक में भूसा खरीद रहे हैं। इस कारण जिले में भूसे के दाम बीते दो महीने में ढाई गुना तक बढ़ गए हैं। पहले जो भूसा 800 रुपए क्विंटल था वह अब 2000 से 2100 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया है। भूसे के संकट की भनक जिला प्रशासन को भी थी, इसीलिए कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने 27 नवंबर को भूसे की दूसरे राज्यों में सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन यह प्रतिबंध कागजों में ही सीमित रहा। हर रोज दर्जनों ट्रैक्टर-ट्राली व ट्रकों में भरकर भूसा राजस्थान व दिल्ली जा रहा है, लेकिन प्रशासन, पुलिस या कृषि विभाग ऐसे एक भी वाहन पर कार्रवाई कर सका।

गेहूं की खेती तीन गुना घटी | भूसे का संकट गेहूं की फसल की कटाई के साथ ही पूरी तरह खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि मुरैना सहित पूरे चंबल अंचल में इस साल गेहूं की फसल का रकबा बहुत घट चुका है। सरसों के भाव अच्छे होने के कारण गेहूं करने वाले किसानों ने भी सरसों की खेती की है। इसे इस तरह समझें कि बीते साल मुरैना जिले में 99 हजार 167 हेक्टेयर जमीन में गेहूं की खेती हुई थी। इस साल केवल 33 हजार 421 हेक्टेयर जमीन में गेहूं की खेती हुई है। यानी बीते साल की तुलना में एक तिहाई कम रकबा रह गया, इसका असर भूंसे की पैदावार, उसके दाम और मवेशियों की उपलब्धता पर साफ दिखेगा।

पशुपालकों की फजीहत

हर साल गेहूं की फसल के सीजन में भूसे की कमी होती है, लेकिन भूसे के दाम इस साल जितने बढ़े हैं वैसा कभी नहीं हुआ। बीते साल सर्दी के दिनों में भूसा 800 से 1000 रुपए क्विंटल में बिका था। इस साल भूसे के दाम 2000 से 2100 क्विंटल तक पहुंच गया है, जबकि गेहूं के दाम 2000 रुपए और बाजरा के भाव 1500 रुपए क्विंटल के आसपास चल रहे हैं। गरीब परिवारों को तो सरकार पीडीएस दुकान से एक रुपए किलो में बाजरा, गेहूं व चावल तक दे देती है, लेकिन गरीब पशुपालकों अपनी मवेशी के लिए चारा आसानी से नहीं मिल रहा।

इस साल बाढ़ के कारण भूसे का संकट हुआ है। कमी के कारण ही भूसे के परिवहन पर प्रतिबंध है, अगर इसके बाद भी चोरी छिपे भूसा जा रहा है तो इस पर रोक लगाने व कार्रवाई करने के लिए राजस्थान बार्डर पर सतर्कता बढ़ाई जाएगी। **बी कार्तिकेयन,कलेक्टर, मुरैना**

इन तीन कारणों से भूसे का संकट

- अगस्त में चंबल व क्वारी नदियों में ऐसी भीषण बाढ़ आई कि हजारों बीघा खेत व 250 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। खेतों व गांवों में स्टाक किया गया भूसा बह गया या फिर भीगकर खराब हो गया।
- भूसे का उपयोग ईंट पकाने वाली चिमनियों में होने लगा है। मुरैना से सटे उप्र के सनिया-मनिया और राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र की चिमनियों से मुरैना से हजारों ट्राली भूसा खपा है।
- सर्दी में बारिश के कारण बाजरा की करब भीगने के कारण उसमें फफूंद लग गई, इसे खाने से मवेशियों की मौत की घटनाएं सामने आईं, इसलिए बाजरा की करब को चारे में उपयोग नहीं किया रहा और गेहूं के भूसा की मांग अचानक से बढ़ गई।

-बोवनी से पहले किसान जानें विधि

मूंगफली की खेती से कमाएं लाभ गर्मी में भी किसान करे बोवनी

भोपाल। संवाददाता

गेहूं, चना, सरसों इत्यादि कई रबी की फसलों की कटाई के बाद खेत खाली होने के बाद यदि किसान जायद की फसल लेना चाहते हैं और अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो गर्मी के इस मौसम में मूंगफली की बोवनी कर सकते हैं। अभी तक किसान केवल बरसाती मौसम में ही खरीफ फसल के रूप में मूंगफली की बोवनी करते थे और पैदावार लेते थे। लेकिन जिन किसानों के पास पर्याप्त पानी की सुविधा है वे गर्मियों के दिनों में भी तीसरी गर्मी के रूप में मूंगफली की पैदावार ले सकते हैं। रबी फसल की कटाई के बाद मार्च के अंत में इसकी बोवनी कर सकते हैं। गर्मी में इसका उत्पादन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उपयुक्त भूमि

यदि आप मूंगफली की बोवनी कर रहे हैं तो इसके लिए भूमि का पीएच मान लगभग 6 से 7 के बिच होना चाहिए। बुलई दोमट मिटटी में मूंगफली की बुवाई करना चाहिए। इस मिटटी में इसका उत्पादन अच्छा होता है। गहरी काली मिट्टी में मूंगफली की बोवनी नहीं करनी चाहिए।

उपयुक्त समय

यदि आप मूंगफली की बोवनी करना चाहते हैं तो गर्मी के इस सीजन में जायद गर्मी मूंगफली की बोवनी मार्च के महीने में कर सकते हैं। इस समय किसान भाई मूंगफली की बोवनी करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है।

उपयुक्त किस्म

यदि आप जायद इस सीजन में मूंगफली की बोवनी करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्नत किस्म का चयन करना चाहिए। जायद सीजन में मूंगफली बोवनी की कुछ प्रमुख किस्म जीजी-20, टीजी-37 ए, टीपीजी-41, जीजी-6, डीएच-86, जीजेजी-9 इन प्रमुख किस्म चयन किसान भाई गर्मी के मौसम में मूंगफली बोवनी के लिए कर सकते है।

सिंचाई

गर्मियों के मौसम में आप इसकी सिंचाई 5-6 बार कर सकते हैं। आप जब रबी की गर्मी यानी सरसों, चना, मटर तथा मसूर की कटाई कर लें तो फिर खेत की जुताई कर एक बार पलावा कर इसे बो दें। अंकुरण के लगभग 15-12 दिन के उपरांत आप इसकी पहली सिंचाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी सिंचाई 25 से 30, तीसरी 40 से 45, चौथी 55 से 60, पांचवी 60 से 65 एवं छठी 70 से 80 दिनों के अंतराल में करें। अब जब ये तैयार हो जाए तो इसकी गुड़ाई आप हांथ तथा खुरपी से करें।

ऐसे करें खुदाइ

किसान इसकी खुदाई उस दौरान करें जब इसकी पत्तियों का रंग पीला हो जाए एवं इसके अंदर परियों का एनिन का कलर भी उड़ जाए। वही जब बीज के ऊपर भाग रंगीन हो जाए तो आप खेत की सिंचाई कर फलियों को पौधों से अलग कर लें। जब इसकी खुदाई कर दें तो इसे धूप में रखें ताकि ये सुख जाए और आप इसे रख सकें।

भंडारण

जब आप इसका भंडारण कर रहें हैं तो इसका ध्यान रखें। अगर ये तेज धूप में सुख रहा है तो इससे अंकुरण का हास्य भी होता है। इसके पके हुए दाने में नमी की मात्रा 10 प्रतिशत से अधिक नही और 8 से कम नही होना चाहिए।

जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि में 7 पौधे फूलों से लदे, ग्रोथ भी अच्छी

शिमला सेब के पौधों पर खिले फूल, महाकोशल में बड़ी क्रांति

जबलपुर। संवाददाता

मध्यप्रदेश में भी शिमला की तरह सेब की खेती संभव हो सकेगी। प्रदेश की जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि के वैज्ञानिक खेती किसानी में नई संभावना तलाशने में जुटे हैं। 14 महीने पहले रिसर्च के तौर पर विवि कैम्पस में रोपे गए सेब के पौधों में फूल खिल आए हैं। अब इससे फल बनने की प्रोसेस शुरू होगी। फल भी उम्मीद के मुताबिक आए तो ये महाकोशल के लिए बड़ी क्रांति होगी। जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. मोनी थॉमस ने बताया कि शुरुआती रिजल्ट उत्साह बढ़ाने वाले हैं। पूर्व में अमरकंटक में सेब और नाशपाती की कई वर्षों पहले खेती होती रही है। कोविड के समय में कृषि विवि में 14 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला से सेब की हरिमन-99 किस्म के 10 पौधे मंगवाए थे। तीन सूख गए। 7 पौधों में अच्छी ग्रोथ हुई है।

सेब का पौधा 45 डिग्री तापमान सहने में सक्षम

सभी पौधों में अच्छी मात्रा में फूल आए हैं। ये फल में परिवर्तित हो गए तो इस तापमान में सेब की खेती करना संभव हो जाएगा। ये हमारे किसानों के लिए वरदान साबित होगा। हरिमन-99 किस्म के सेब का पौधा 45 डिग्री का तापमान आसानी से सहन कर सकता है। अभी तक की संभावना अच्छी है। उम्मीद है कि फूल आए तो फल भी आएंगे। इससे यहां भी सेब के बागान तैयार करने का रास्ता खुलेगा।

सेब के लिए अनुकूल जबलपुर का मौसम

सेब के लिए जबलपुर का मौसम काफी अनुकूल माना जा रहा है। यहां साल भर धूप होती है। मिट्टी का पीएच 5 से 7 के बीच होनी चाहिए। यहां की मिट्टी भुरभुरी है। इसके पौधे में पानी नहीं लगना चाहिए। पौधे के लिए ठंड जरूरी है, लेकिन पाला नहीं पड़ना चाहिए। यहां ठंड में तापमान औसतन 7 से 20 डिग्री तक रहता है। सेब के पौधे डेढ़ से तीन साल में फलने लगते हैं। फूल आने और फल पूरी तरह तैयार होने की प्रोसेस में 130 से 135 दिन लग जाते हैं।

अंचल के किसान पंजाब की तरह करने जा रहे खेती, किसानों ने 7000 हेक्टेयर में धान की बोवनी की शुरू

पंजाब की तर्ज पर चंबल अंचल में भी धान की बोवनी

ग्वालियर। संवाददाता

क्षेत्र के किसान कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए अब जागरूक हो रहे हैं। क्षेत्र की बात करें तो डबरा और भितरवार ब्लॉक में अभी तक वर्ष में दो फसलें ही होती थी, लेकिन अब क्षेत्र के किसान पंजाब की तर्ज पर एक वर्ष में तीन बार खेती कर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। वर्तमान में डबरा और भितरवार ब्लॉक में धान और गेहूं की फसलें होती थी, लेकिन अब भितरवार के दो दर्जन से अधिक गांवों और चीनोर और डबरा के दो दर्जन से अधिक गांव के किसानों की ओर से मटर चना सरसों की फसल कटने के बाद सीधे ही धान की बोवनी शुरू कर दी है। इससे दोनों ही ब्लॉकों में धान की बंपर आवक होगी। अभी तक यह फसलें अधिकांश पंजाब क्षेत्रों में देखने को मिलती थी। पंजाब की तर्ज पर ही क्षेत्र के किसान कृषि को लाभ का धंधा बनाने जा रहे हैं। क्षेत्र में कुल 7000 हैक्टेयर में किसानों ने इस बार धान की बोवनी का कार्य शुरू कर दिया है।

औद्योगिक इकाई भी बनी वजह

वर्तमान में डबरा भितरवार रोड पर आधा दर्जन से अधिक औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं। जुलाई अंत तक यह फसल पक कर तैयार हो जाएगी और इन फसलों का दाम भी अच्छा मिलेगा किसानों ने बताया 27 सौ से 3000 प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का दाम मिल जाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गर्मी में इस फसल को तैयार करने में फसलों में रोग भी कम लगता है।

इन गांव में शुरू हुआ काम

विकासखंड के अंतर्गत आने वाले चरखा, सहारन, जोरा श्यामपुर, देवगढ़, बांसवाड़ा, खेड़ा, टाका, चीनोर, प्रेमपुर आदि ऐसे गांव हैं जहां पर धान की पैदावार किसानों ने शुरू कर दी है। किसानों ने बताया कि जुलाई में फसल कटने के बाद फिर से उनकी ओर से धान की फसल तैयार कर ली जाएगी।

जुलाई में तैयार होगी फसल | किसान रामनरेश हाकिम सिंह जनवेद सिंह ने बताया कि उनके यहां पर सरसों और चना की फसल कटने के बाद उन्होंने धान की बोवनी का कार्य शुरू कर दिया है। अपने निजी संसाधनों से यह खेती कर रहे हैं। जुलाई लास्ट महीने तक धान की फसल पककर तैयार हो जाएगी और उस समय इसे बेचने पर अधिक दाम भी मिलेंगे किसानों ने बताया कि 1509 क्रांति सुगंधा आदि फसल की पैदावार की जा रही है।

यह बात सही है कि पंजाब की तर्ज पर किसानों की ओर से धान की खेती शुरू की गई है। 7000 हेक्टेयर में किसानों ने धान की बोवनी का कार्य शुरू कर दिया है। यह आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ किसानों के यहां फसल की कटाई पूरी तरह से नहीं हुई है।

विनोद तिवारी, प्रभारी कृषि विभाग भितरवार

गर्मी में धान की नर्सरी तैयार कर ली गई है और नर्सरी को रोपने के लिए खेतों को तैयार किया जा रहा है। खरीफ सीजन की तुलना में इस सीजन में धान की लागत कम आती है और उत्पादन खरीफ सीजन की तरह होता है। बस पानी की ही ज्यादा जरूरत धान को पड़ती है।

प्रदीप शर्मा, किसान, ग्राम सहारण

-ई-बे इंडिया, फ्लिपकार्ट, ईईपीसी के साथ हुआ एमओयू

उद्योगों को बढ़ावा देने निर्यात सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा

संवाददाता, भोपाल।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल-2021 से जनवरी-2022 तक मध्यप्रदेश में 6.44 बिलियन अमेरिकन डॉलर का निर्यात किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष के अंत तक मध्यप्रदेश का कुल निर्यात 8 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक रहने का अनुमान है। प्रदेश में निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा विगत वर्ष वाणिज्य उत्सव में एमपी ट्रेड पोर्टल तथा एक्सपोर्टस हैल्पलाइन का शुभारंभ किया गया था। इस माह के प्रारंभ में मप्र ट्रेड प्रमोशन कॉउन्सिल का गठन किया गया। प्रदेश की सरल औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से इस वर्ष निर्यात में 25 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। आत्मनिर्भर मप्र को संबल देने के लिए एक जिला-एक उत्पाद के तहत निर्यात सुविधाओं को विस्तृत किया जाएगा।

ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन का शुभारंभ

मंत्री ने मप्र ट्रेड कॉन्फ्रेंस-2022 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन का शुभारंभ किया। प्रदेश में इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भता की ओर ले जाने के लिए ईईपीसी, इंडिया द्वारा एमपी इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., के सहयोग से एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमे एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक जॉन किंग्सले द्वारा फ्लिपकार्ट, ई-बे एवं ईईपीसी इंडिया के साथ एमओयू साइन किए गए।

चैयनित उत्पदों को मिलेगी पहचान

मंत्री दत्तीगांव ने कहा कि फ्लिपकार्ट तथा एमपीआईडीसी के मध्य एमओयू से प्रदेश के नवीन उद्यमियों, हस्थशिल्पियों, कारीगरों, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्व-सहायता समूहों को बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही यह मध्यप्रदेश शासन की एक जिला-एक उत्पाद योजना में चयनित उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

ई-बे इंडिया के साथ साझेदारी से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादनों को प्रदर्शित करने, प्रदेश के सामाजिक- आर्थिक विकास तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा मिलेगा। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफइंडिया प्रदेश में इंजीनियरिंग एवं एडवांश मेन्यूफेक्चरिंग उद्योगों के निवेश एवं प्रदेश में उत्पादित इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने का कार्य करेगी, जिससे प्रदेश में रोजगार सृजन होगा।

नया बाजार उपलब्ध कराएंगे

एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक जॉन किंग्सले ने कहा कि मप्र व्यापार संवर्धन परिषद के गठन से अंतरराष्ट्रीय व्यापार हितों और सरकारी निकायों के बीच संबंधों को मजबूत करके प्रदेश के उत्पादों के लिए नया बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में ईईपीसी इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुरंजन गुप्ता, एसईजेड इंदौर के विकास आयुक्त डॉ. एसके बंसल, ईईपीसी इंडिया के रीजनल चैयरमेन के.एल. ढींगरा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

- मंत्री समूह की हुई बैठक में गृहमंत्री नरोत्तम ने कहा

गौ-शालाओं के विकास के लिए समेकित योजना जरूरी

संवाददाता, भोपाल।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि गौ-वंश संवर्धन के साथ ही गौ-शालाओं का सर्वसुविधायुक्त विकास भी जरूरी है। गायों के बेहतर संरक्षण के साथ गोबर के समुचित उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चाहिए। गृह मंत्री मंत्रालय में सड़कों पर विचरण करने वाले पशुओं की बेहतर व्यवस्था और गोवर्धन योजना समिति संबंधी मंत्री समूहों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, पशुपालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल, एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा और उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह भी उपस्थित थे। मंत्री समूह की बैठक में गौ-शालाओं के विकास, गौ-संरक्षण और गोबर के समुचित उपयोग पर विस्तार से चर्चा हुई।

सीएम के समक्ष होगा प्रजेंटेशन

अपर मुख्य सचिव पशुपालन जेएन कंसोटिया ने गौ-वंश संवर्धन के लिए की जा रही कार्रवाई का प्रस्तुतिकरण दिया।

बैठक में गौ-शालाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गौ-शालाओं में ही गोबर और गौ-मूत्र से विभिन्न उत्पादों के निर्माण और विपणन की व्यवस्था संबंधी विभिन्न सुझाव दिए गए। मंत्री ने सुझावों को कार्रवाई विवरण में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सुझावों और अनुशंसाओं के आधार पर तैयार किया गया प्रजेंटेशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो-2022 मई में

नई दिल्ली/भोपाल।

जैविक क्षेत्र पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो-2022 का आयोजन 26 से 28 मई तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इस तीन दिवसीय आयोजन का उद्देश्य किसानों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन, विपणन और आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों के साथ भारत की प्राचीन कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में लगभग 1 लाख किसान, 10 से अधिक देशों की 600 से अधिक कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद है। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो में प्रदर्शनी के अलावा, 20 से अधिक सम्मेलन सत्र प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों/जैविक कृषि विशेषज्ञों और जैविक कृषि में कार्यरत प्रगतिशील किसानों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। प्रदर्शनी में देश के लगभग हर राज्य की भागीदारी, किसानों, अनुसंधान केंद्रों और कृषि शिक्षण विश्वविद्यालयों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है।

भोजपाल महोत्सव मेले में कवि सम्मेलन में हरिओम पवार सहित अन्य कवियों ने दी प्रस्तुति

कविता को रच, छंद को प्यार करूं, मां शारदे ऐसा वरदान दे...

संवाददाता, भोपाल। कविता को रच छंद को प्यार करूं मां शारदे ऐसा वरदान दे की प्रस्तुति से कवि शशिकांत यादव ने कविता काठ की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता अरुण यादव, पूर्व मंत्री एंदल सिंह कंसाना, खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष जितेंद्र लिटोरिया रहे। विशिष्ठ अतिथि विधायक रामेश्वर शर्मा, मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी, खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, रामबाबू शर्मा, बसंत गुप्ता, राजेंद्र सिंह यादव, दीपक गुप्ता के साथ ही मेला अध्यक्ष सुनील यादव, मेला संयोजक विकास वीरानी, महामंत्री हरीश कुमार राम रहे।

हास्य कविताओं की बौछार...- राजधानी के भेल दशहरा मैदान पर चल रहे भोजपाल महोत्सव मेले में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देश के जाने माने वीर रस के कवि हरिओम पवार के साथ ही शशिकान्त यादव, कविता तिवारी, शम्भू शेखर और धर्मेंद सोलंकी ने मेला मंच पर अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी। इस मौके पर जहां कुछ कवियों ने हस्य की बौछार की तो वहीं पवार ने देश भक्ति से ओतप्रोत कविताओं की प्रस्तुति देकर लोगों में जोश भरा। गौरतलब है कि मेले में आने वाले यह सभी कवि देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेशों में भी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर फोकस

मेला अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि मेले में लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वीरेंद्र तिवारी, दीपक बैरागी, दीपक शर्मा, सुनील शाह, महेंद्र नामदेव, चन्दन वर्मा, अखिलेश नागर, शैलेंद्र सिंह जाट, विनय सिंह, केश कुमार शाह, मधु भवनानी, देवेंद्र चौकसे, इंद्रजीत, नीलम चौकसे, गोपाल शर्मा, गौरव जैन, सुनील वैष्णव सहित समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।

केवीके टीकमगढ़ में अजोला उत्पादन तकनीक पर दिया गया प्रशिक्षण

संवाददाता, टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केन्द्र, टीकमगढ़ में अजोला उत्पादन तकनीक पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक टीकमगढ़ राकेश गिरी गोस्वामी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राकेश गिरी ने किसानों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। प्रमुख वैज्ञानिक डॉ बीएस किरार ने किसानों को जैविक खेती एवं अजोला का उपयोग जैविक रूप से कैसे करें इसकी जानकारी प्रदान की। डॉ आरके जैन, वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, मिनौरा फार्म द्वारा किसानों को पशु में होने वाले रोगों एवं बिमारियों पर प्रशिक्षण दिया। वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति द्वारा प्राकृतिक खेती कैसे की जाए एवं ब्रम्हास्त्र, घनाजीवामृत कैसे बनाए इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। डॉ. सुनील कुमार जाटव वैज्ञानिक केवीके टीकमगढ़ द्वारा किसानों को अजोला उत्पादन करने के लिए पक्का टांका निर्माण करने के लिए 10 फीट लम्बाई 3 फीट चैड़ाई एवं 2 फीट ऊंचाई का पक्का टांका निर्माण करने की सलाह दी। अजोला एक जलीय फार्म है जो कि पानी की सतह पर तैरता रहता है। इसको छाया में उगाया जाता है।

दुधारू पशुओं में परजीवी रोगों पर नियंत्रण कर बढ़ाएं दुग्ध उत्पादन

संवाददाता, दतिया। कृषि विज्ञान केंद, दतिया में पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण अंतर्गत पशुधन में परजीवी रोगों के प्रबंधन विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन गत दिवस केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. आरकेएस तोमर के मागदर्शन में एवं डॉ. रूपेश जैन प्रशिक्षण समन्वयक के तकनीकी मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिन विषय विशेषज्ञ डॉ. रूपेश जैन द्वारा दुधारू पशुओं में परजीवियों द्वारा होने वाले प्रमुख रोग के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। डॉ. जैन ने बताया कि पशुओं में मुख्य रूप से गोल कृमि, चपटे कृमि एवं पत्ता कृमियों के प्रबंधन द्वारा दुग्ध उत्पादन में 15-20 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए साईपर मैथ्रिन, फ्लूमैथ्रिन, डेल्टामैथ्रिन दवा 3मिली एक लीटर पानी में घोल बनाकर पशुओं के शरीर पर लगाना चाहिए। इससे बाह्य परजीवियों का नियंत्रण किया जा सकता है। अंत: परजीवियों के नियंत्रण के लिए एल्बेन्डेजोल अथवा फेनबेल्डेजोल दवा 7.5 मिग्रा. प्रति किग्रा शरीर भार के हिसाब से दुधारू पशुओं को देना चाहिए। डॉ. विवेक अग्रवाल द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को हर तीन महीने में एक बार दुधारू पशुओं की डीवार्मिंग करने की सलाह ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से दी गई।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा

संवाददाता, बैतूल।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि डॉ. एसके चौधरी उप महानिदेशक (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्लीए विशिष्ट अतिथि डॉ. एसआरके सिंह संचालक अटारी जोन-9 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जबलपुर शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. दिनकर प्रसाद शर्मा संचालक विस्तार सेवाएं, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर द्वारा की गई। डॉ. टीआर शर्मा प्रधान वैज्ञानिक ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर, डॉ. एसके पन्ना से प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र छिंदवाड़ा एवं डॉ. आरके झाडे वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र छिंदवाड़ा-2 के साथ केन्द्र पर पदस्थ सभी वैज्ञानिकों ने भाग लिया। प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण और कृषि को टिकाऊ एवं लाभदायक बनाने के लिए यह परिचर्चा आयोजित की गई। केन्द्र प्रमुख डॉ. वीके वर्मा द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा के महत्व पर प्रकाश डाला। कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रमुख कार्यादेशों के अतिरिक्त कृषक हित में चलाए जा रहे प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण आरडी बारपेट, वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया। परिचर्चा के पूर्व सभी विशिष्ट अतिथियों द्वारा केन्द्र के प्रांगण मे कृषि विज्ञान केन्द्र के सम्पर्क कृषकों/ग्रामीण युवाओं द्वारा कृषि आधारित उद्यम के उत्पादों की प्रदर्शनी और विभिन्न प्रदर्शन इकाइयां जैसे-पौधशाला, अमरूद, आम, नीब, मातृ वृक्ष उद्यान, बकरी पालन इकाई, सीड हब परियोजना, फसल संग्रहालय, अजोला इकाईए वर्मी कम्पोस्ट इकाई, उन्नत कृषि यंत्र प्रदर्शन इकाई, आदि का निरीक्षण किया। प्राकृतिक खेती के लिये रसायनों के विकल्प के रूप मे जैव उत्पाद इकाई का शुभारंभ उपमहानिदेशक द्वारा किया गया। प्रांगण के निरिक्षण के बाद प्रौधौगिकी पार्क मे सभी अतिथियों द्वारा पौधरोपण भी किया गया। इस कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा में जिले के अलग-अलग क्षेत्र जैसे- पशुपालन, शहद उत्पादन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, गन्ना उत्पादन, फल उत्पादन, बीज उत्पादन, सब्जी उत्पादन, जैविक कृषि, एफपीओ आदि के प्रगतिशील 85 कृषकों ने भाग लिया। इन सभी कृषकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की तकनिकी एवं व्यवहारिक पहलुओं पर मंचासीन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उप महानिदेशक द्वारा जिले के कृषकों को आश्वस्त किया कि वे कृषकों की जायज समस्याओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एवं भारत सरकार के उपयुक्त मंचों पर रखेंगे। विशिष्ट अतिथि संचालक अटारी जोन-9 द्वारा केन्द्र की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से इस केन्द्र को सभी संभव सहायता की जाएगी। संचालक विस्तार सेवाएं, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का विश्वविघालय परिवार की ओर से शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिंन्ह देकर अभिनंदन किया।

यह रहे मौजूद

कार्यक्रम के अंत में डॉ. संजीव वर्मा द्वारा सभी का आभार प्रकट किया गया। इस कार्यक्रम में 85 किसानों ने भाग लिया। केन्द्र के सभी वैज्ञानिक डॉ. मेघा दुबे, डॉ. संजय जैनए इंजी. नेपाल बारस्कर, सौरब मकवाना और राजू सलामे ने सक्रिय रूप से शामिल हुए।

-ऑपरेशन ग्रीन्स योजना:काला नमक धान की खेती पर जोर

काला चावल को बढ़ावा देने 12 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर

» 22 खराब होने वाली फसलों की पहचान की गई

» किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बजट का उपयोग

संवाददाता। भोपाल/नई दिल्ली

काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर के तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दस पड़ोसी जिलों में उगाया जाता है। यह एक सुगंधित चावल की किस्म है जिसे आम तौर पर किसानों को चावल की अन्य किस्मों की तुलना में बेहतर कीमत मिल जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के तहत काला नमक चावल को बढ़ावा दे रही है और काला नमक चावल को बढ़ावा देने के लिए 12.00 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस बात जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में किया। तोमर ने बताया की स्थिति आकलन सर्वेक्षण एनएसओ द्वारा कुछ निश्चित अंतराल पर ही किया जाता है। पिछले दो एसएएस कृषि वर्ष, जुलाई 2012-जून 2013 और जुलाई 2018-जून 2019 के लिए किए गए थे।

कृषि परिवारों की आय पर अंतिम उपलब्ध अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण पर आधारित हैं। (एनएसएसओ) 77वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2019) के दौरान किया गया। सर्वेक्षण के परिणामों के मुताबिक सभी स्रोतों से प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10218 रुपए थी। तोमर ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग द्वारा किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए आरई 2020-21 चरण में 116757.92 करोड़ का प्रावधान रखा गया था, जिसमें से 108622.51 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया था।

अधिक उपज वाले उन्नत बीज उपलब्ध

51 राज्य और केंद्रीय कृषि और बागवानी विवि और 65 फसल आधारित आईसीएआर संस्थानों और उनके क्षेत्रीय स्टेशनों, 726 कृषि विज्ञान केंद्रों, राष्ट्रीय बीज के 3000 डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से जिला/तालुका स्तर पर किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए एक मजबूत नेटवर्क है। कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 17 राज्य बीज निगम, 6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, कृभको, नैफेड, नफ्ल, हिल, एनडीडीबी, लगभग 550 निजी बीज कंपनियां, एफपीओ और एनजीओ शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुछ संस्थानों ने किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन बीज पोर्टल विकसित किए हैं। सरकार ने दलहन, तिलहन और बाजरा के गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए बीज केंद्र भी शुरू किए हैं।

सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55 फीसदी और अन्य किसानों के लिए 45 फीसदी की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, कुछ राज्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में बताया कि ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के दीर्घकालिक उपायों के तहत सहायता के लिए 22 खराब होने वाली फसलों की पहचान की गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन आंकड़ों के आधार पर प्रमुख उत्पादक राज्यों तथा जिलों में 22 फसलों के लिए समूहों की पहचान की गई है। यह योजना मांग आधारित है और इस योजना के तहत कोई राज्यवार या जिलेवार बजट आवंटित नहीं किया गया है।

गायों के चरने के साथ ही संतों के रुकने की रहेगी व्यवस्था

चार करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च

इंदौर के पास दस बीघा जमीन पर बनेगा गौ-तीर्थ

संवाददाता, इंदौर।

इंदौर के पास श्रीश्री विद्याधाम मंदिर ट्रस्ट मंडल पूज्य श्री भगवन गौ-तीर्थ बना रहा है। प्रारंभिक रूप से 4 करोड़ रुपए इसे बनाने में खर्च होंगे। गौ-तीर्थ में पहले 200 फिर धीरे-धीरे 1200 गायों के रहने, खाने के साथ ही अन्य सभी सुविधाएं रहेगी। इस तीर्थ को कुछ ऐसा बनाया जा रहा है कि यहां अगर किसी को गौ-वंश के बीच समय बिताना है, तो वे यहां कुछ दिन रुक भी सकेंगे। इस काम की शुरुआत हो चुकी है। यहां बाउंड्रीवॉल बनकर तैयार हो गई है। इसके साथ ही यहां भूसा घर बनाया जा रहा है।

यह गौ-तीर्थ श्रीश्री विद्याधाम मंदिर से 14 किमी दूर हतोद के पास ग्राम काकरिया बोडिया में बन रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य गौ-वंश की सेवा, विकास और संवर्धन है। यहां गायों को खुला रखा जाएगा। 10 बीघा जमीन पर तीर्थ को बनाया जाएगा। इसमें गायों के लिए कई सुविधाएं रहेगी। तीर्थ तैयार होने पर श्रीश्री विद्याधाम मंदिर से पहले 200 गायों को वहां रखा जाएगा बाद में 1200 गायों को रखा जाएगा। यहां 24 घंटे उनके पानी-चारे की व्यवस्था रहेगी।

उद्यान और नक्षत्र वाटिका - पं. शर्मा और कोषाध्यक्ष राजेंद्र महाजन ने बताया गौ-तीर्थ में एक उद्यान बनाया जाएगा। इसके अलावा यहां पेड़ों की नक्षत्र वाटिका भी तैयार की जाएगी। साथ ही यहां शिव मंदिर या कृष्ण मंदिर बनाने की भी योजना है। यहां गौ-वंश के स्टैच्यू भी लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गौ-तीर्थ का निर्माण ट्रस्ट के सहयोग और फिर जन सहयोग से किया जाएगा।

संतों के रुकने की व्यवस्था

ट्रस्ट मंत्री पं. दिनेश शर्मा और महामंत्री पूनमचंद अग्रवाल के मुताबिक 10 बीघा जमीन को दो हिस्सों में बांटा है। इसमें 5 बीघा जमीन गायों के चरने के लिए रहेगी। इसके अलावा यहां दो कॉटेज बनाए जाएंगे, जिसमें संत या आमजन आकर कुछ दिन रुक सकेंगे। साथ ही बच्चों के लिए प्ले जोन भी बनाया जाएगा। आधा बीघा जमीन पर एक तालाब बनेगा। यहां आने वाले लोगों के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

मंदिर में 5 गौ-शालाएं, 400 गाय

उन्होंने बताया फिलहाल श्रीश्री विद्याधाम मंदिर में 5 गौ-शालाएं बनी हैं, जिसमें 400 गाय हैं। यहां रोजाना कई लोग गाय को चारा खिलाने आते हैं। गौशाला में गायों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनके पानी, चारे के साथ ही गर्मी में पंखों की भी व्यवस्था यहां है। फिलहाल यहां बाहर से गाय नहीं ली जा रही है। अगर किसी को गोदान करना होता है, तो वे यहीं की गाय को दान कर देते हैं।

भिंड जिले में 1200 हेक्टेयर में किया जाएगा पौधारोपण

चंबल के बीहड़ की अब हरियाली से होगी पहचान

संवाददाता, भोपाल। चंबल के बीहड़ में मध्य प्रदेश सरकार हरियाली फैलाने की तैयारी कर रही है। दतिया जिले में प्रस्तावित मां रतनगढ़ बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना में 1248 हेक्टेयर वन भूमि डूब रही है। इसमें बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे, जिसकी भरपाई भिंड जिले में स्थित बीहड़ में की जाएगी। वहां 1200 हेक्टेयर भूमि पौधारोपण के लिए प्रस्तावित की गई है। वन विभाग ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। वहां से मंजूरी मिलते ही विभाग आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। इस प्रयोग के सफल होते ही क्षतिपूर्ति वनीकरण (एक पेड़ काटने के बदले पांच पौधे लगाने) योजना के तहत पौधे रोपने के लिए बीहड़ का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि रतनगढ़ में आकार लेने वाले सिंचाई परियोजना से दतिया जिले के 17, भिंड और ग्वालियर के दो सौ गांवों में सिंचाई हो सकेगी। परियोजना से 78 हजार 484 हेक्टेयर में कृषि भूमि की सिंचाई की जाएगी।

बीहड़ में पर्यावरण संरक्षण

दो दशक पहले तक चंबल के बीहड़ कुख्यात डकैतों की मौजूदगी के लिए जाने जाते थे, पर राज्य सरकार अब इसकी पहचान बदलने जा रही है। बीहड़ में अब पर्यावरण संरक्षण के काम होंगे। पहल भिंड जिले से की जा रही है। पौधे लगाने के लिए राशि जल संसाधन विभाग देगा। वहीं कैंपा फंड वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण से भी राशि का प्रबंध किया जाएगा।

पौधारोपण का रास्ता

सरकार ने भी वन विभाग से कहा है कि चंबल के बीहड़ में बड़े स्तर पर सरकारी भूमि खाली है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए भूमि देने के बदले वनीकरण क्षतिपूर्ति के लिए यह भूमि दी जाती है, तो उसे अस्वीकार न करते हुए यह प्रयास करें कि उस पर कैसे और किस प्रजाति के पौधे रोपे जा सकते हैं।

जैविक खेती से जुड़ा सेंटर जबलपुर से नागपुर ले जाने की तैयारी

जबलपुर। मध्यप्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा प्रदेश सरकार ही नहीं केंद्र भी कई योजनाओं को जमीन पर लाने में जुटा है। वहीं हकीकत यह है कि जबलपुर के किसानों को पिछले 30 साल से जैविक खेती का प्रशिक्षण देने वाले संस्थान को सेंटर बनाने के लिए जमीन तक नहीं मिली। इस वजह से सेंटर को जबलपुर से उठाकर नागपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके विरोध में अब तक न तो कोई जनप्रतिनिधि आगे आया है और न ही कोई किसान संगठन। हालांकि किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय के इस निर्णय का विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल शताब्दीपुरम विजय नगर में किराए के भवन में चले रहे रीजनल सेंटर आफ आर्गेनिक फार्मिंग को नागपुर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

जबलपुर के रीजनल सेंटर आफ आर्गेनिक फार्मिंग को नागपुर शिफ्ट करने संबंधित जानकारी मेरे संज्ञान में आई है। इस मामले को मैं केंद्रीय कृषि मंत्री से बात करूंगा। केंद्रीय कृषि मंत्री मध्यप्रदेश के ही हैं और मुझे विश्वास है कि वे इसे नागपुर में शिफ्ट नहीं होने देंगे।
-कमल पटेल, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-7000141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)